



Daily करेंट अफेयर्स

» 23 जून 2025



NATIONAL AFFAIRS / GOVERNMENT SCHEME

1. सरकार मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए WII-SACON में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी।



21 जून, 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE) की स्थापना की घोषणा की। इस उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी भारतीय वन्यजीव संस्थान और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र (WII-SACON) द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी, जिससे भारत को वन्यजीवों से संबंधित मौतों को रोकने के लिए उन्नत, विज्ञान समर्थित समाधान मिलेंगे।

● यह लॉन्च 2021 की सलाह और 2022 के संघर्ष शमन संबंधी दिशा-निर्देशों पर आधारित है, ऐसे समय में जब बाघ और हाथी के हमलों से मौतें बढ़ रही हैं। अकेले 2024 में, बाघों से संबंधित 74 मौतें हुईं - 2023 में 86 और 2022 में 111 से बढ़कर - महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश पर इसका गंभीर असर पड़ा। इसी तरह, 2023-24 में हाथियों से संबंधित 628 मानव मौतें दर्ज की गईं, जिनमें से ओडिशा में 154 ऐसी घटनाएं हुईं।

● उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) AI -संचालित उपकरणों के विकास और तैनाती पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें कैमरा ट्रैप, GIS मैपिंग और वास्तविक समय ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं, जो मानक संचालन प्रक्रियाओं, लक्षित सार्वजनिक संवेदीकरण अभियानों और संघर्ष स्थितियों को रोकने और

प्रबंधित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीमों द्वारा समर्थित हैं।

Key Points:-

(i) घोषणा के दौरान, मंत्री यादव ने कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में गिरवा नदी में सात नवजात घड़ियाल को छोड़ कर उत्तर प्रदेश में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल के संरक्षण के लिए एक प्रयास भी शुरू किया। यह पहल एक व्यापक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और नदी पुनरुद्धार मिशन का हिस्सा है।

(ii) दुधवा टाइगर रिजर्व में आयोजित कार्यशाला में मंत्री यादव ने थारू आदिवासी समुदाय और विशेष बाघ संरक्षण बल के सदस्यों के साथ बातचीत की, जिसमें पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और अग्रिम पंक्ति की अंतर्दृष्टि को एकीकृत किया गया। ये परामर्श - 25-30 विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों के साथ - CoE की संघर्ष शमन रणनीति और नीति रोडमैप को सूचित करेंगे।

(iii) अगले कदमों में संघर्ष के हॉटस्पॉट पर AI -आधारित सिस्टम को चालू करना, जिला-स्तरीय त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयों की स्थापना करना, निरंतर जन जागरूकता अभियान शुरू करना और मुआवज़ा और राहत के प्रबंधन के लिए राज्य और जिला समितियों को औपचारिक बनाना शामिल है। इस पहल को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए समुदायों और वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा के लिए निरंतर धन, प्रशिक्षण और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होगी।

2. कर्नाटक की युवा निधि योजना के तहत यादगीर के युवाओं को ₹11.70 लाख मिले, 39,132 लाभार्थियों को सशक्त बनाया गया।



जून 2025 में, कर्नाटक सरकार ने युवानिधि योजना के माध्यम से यादगीर जिले में 39,132 बेरोजगार युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से मासिक वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करते हुए सफलतापूर्वक ₹11.70 लाख वितरित किए।

- इस प्रमुख योजना के तहत, स्नातकों को ₹3,000 प्रति माह मिलते हैं, जबकि डिप्लोमा धारकों को ₹1,500 प्रति माह मिलते हैं, जो दो साल तक या रोजगार मिलने तक - जो भी पहले हो। स्नातक होने के छह महीने बाद वितरण शुरू होता है, जो नौकरी की तलाश के दौरान निरंतर सहायता प्रदान करता है।

- लाभार्थियों को प्रत्येक महीने की 25 तारीख को या उससे पहले सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से नौकरी की स्थिति की स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। योजना की अखंडता बनाए रखने के लिए जो लोग नौकरी में पाए जाते हैं, उन्हें तुरंत हटा दिया जाता है।

Key Points:-

(i) जनवरी 2024 में कर्नाटक की पांचवीं गारंटी पहल के रूप में शुरू की गई यह योजना गृह ज्योति, अन्न भाग्य, गृह लक्ष्मी और शक्ति जैसे अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का पूरक है। सरकार ने पहले वर्ष में ₹250 करोड़ निर्धारित किए, जिसे 2025-26 में ₹1,200 करोड़ और 2026 से आगे सालाना ₹1,500 करोड़ तक बढ़ाने का अनुमान है।

(ii) इस पहल से राज्य भर में 1.2 लाख से ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा होगा, जिसमें 5.29 लाख स्नातक और डिप्लोमा धारक शामिल हैं, जिन्होंने 2022-23 और 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण किया है। आधार से जुड़े बैंक खातों के ज़रिए सहज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रक्रिया ने सहायता को सुव्यवस्थित और तेज़ कर दिया है।

(iii) युवानिधि योजना न केवल बेरोजगारी के दौरान तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करती है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देती है। वित्तीय सहायता को वैकल्पिक कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ जोड़कर, यह कार्यक्रम कर्नाटक के शिक्षित युवाओं को नौकरी के अवसरों को प्रभावी ढंग से और आत्मविश्वास से आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है।

3. शिक्षा मंत्रालय ने 2022-23 और 2023-24 के लिए PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की: चंडीगढ़ शीर्ष पर जबकि मेघालय सबसे निचले स्थान पर।



18 जून, 2025 को शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 2022-23 और 2023-24 के लिए परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 रिपोर्ट प्रकाशित की। चंडीगढ़ ने 703-719 अंक प्राप्त किए, जिससे एकमात्र प्राचेस्टा-1 (51-60%) ग्रेड प्राप्त हुआ, जबकि मेघालय अकांशी-3 ($\leq 46\%$) में ~417 से पिछड़ गया, जिससे 302-पॉइंट ($\approx 42\%$) शैक्षिक विभाजन सामने आया।

● PGI 2.0 पूरे भारत में स्कूल शिक्षा का मूल्यांकन 1,000 अंकों के पैमाने पर करता है, जिसे दो श्रेणियों—परिणाम (Outcomes) और शासन एवं प्रबंधन (Governance & Management)—में और छह क्षेत्रों में बाँटा गया है: अधिगम परिणाम (Learning Outcomes - LO), पहुँच (Access - A), बुनियादी ढांचा एवं सुविधाएँ (Infrastructure & Facilities - IF), समानता (Equity - E), शासन प्रक्रियाएँ (Governance Processes - GP), और शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Teacher Education & Training - TE&T)। इसका मूल्यांकन 73 संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जो NAS 2021, UDISE+, पीएम-पोषण (PM-POSHAN), प्रबंधन (PRABAND) और विद्यांजली (Vidyanjali) पोर्टलों से प्राप्त किए गए हैं।

● चंडीगढ़ ने ~688 से ~703-719 तक सुधार किया, जिससे उसे एकमात्र प्रचेस्टा-1 ग्रेड (701-760) प्राप्त हुआ। इसकी सफलता का श्रेय मजबूत आईएफ और GP प्रदर्शन, डिजिटल स्कूल प्रशासन, आधार सीडिंग और व्यावसायिक शिक्षा पहल को जाता है।

● मेघालय ने ~417 अंक प्राप्त किए, जो अकांशी-3 (≤ 460) में गिर गया। यह इस सबसे कम बैंड में एकमात्र क्षेत्र था, जो पहुँच, समानता, बुनियादी ढाँचे और सीखने के परिणामों में गंभीर कमियों की ओर इशारा करता है।

Key Points:-

(i) स्कोर 719 से 417 तक रहा - 302-पॉइंट ($\approx 42\%$) का अंतर, पहले $580/10=60$ प्रति बैंड था। कोई भी क्षेत्र उच्च स्तर (उत्तम या उससे ऊपर) तक नहीं पहुँचा, जो प्रणालीगत सीमाओं को रेखांकित करता है।

(ii) 2022-23 और 2023-24 के बीच 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 24 में सुधार हुआ, जबकि 12 में गिरावट आई। बिहार और तेलंगाना में पहुँच में उच्च सुधार देखा गया; दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना में बुनियादी ढाँचे में लाभ दर्ज किया गया।

(iii) बुनियादी ढाँचे में सुधार के बावजूद, बुनियादी शिक्षा कमजोर बनी हुई है। रिपोर्ट में NEP 2020 और SDG-4

लक्ष्यों के साथ संरेखित LO और इकिटी में केंद्रित हस्तक्षेप की सिफारिश की गई है। सभी कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को ऊपर उठाने के लिए MoE को डेटा-संचालित शासन का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

4. भारत ने तीव्र और सुरक्षित रक्ताधान सुनिश्चित करने के लिए दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री को ई-रक्तकोष के साथ एकीकृत करना शुरू किया।



21 जून, 2025 को, ICMR-NIIH ने भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री शुरू की, जो थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, हीमोफीलिया और इम्यूनोडेफिशिएंसी विकारों जैसे बार-बार रक्त आधान की आवश्यकता वाले रोगियों को लक्षित करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। रजिस्ट्री को अब ई-रक्तकोष के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जो कि DGHS द्वारा प्रबंधित डिजिटल ब्लड-बैंक प्लेटफॉर्म है, ताकि दुर्लभ रक्त प्रकारों के लिए एक एकीकृत, वास्तविक समय तक पहुँच वाला पोर्टल बनाया जा सके।

● रजिस्ट्री ने आणविक परख का उपयोग करके मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता और पुडुचेरी जैसे प्रमुख केंद्रों से 4,000 से अधिक ओ-समूह दाताओं की जांच की है। इसने 600 से अधिक दुर्लभ-एंटीजन-नेगेटिव दाताओं की पहचान की है, जिनमें लगभग 250 को "बहुत दुर्लभ" और लगभग 170 बॉम्बे फेनोटाइप दाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर मांग है (अनुमानित आवश्यकता ~ 120-150 यूनिट/वर्ष)। इन प्रोफाइलों को, अन्य अति-दुर्लभ

प्रकारों जैसे कि P-null और Rh-null के साथ, आसान अनुरोध के लिए एक वेब पोर्टल के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया है।

- 2016 में शुरू किया गया ई-रक्तकोष पहले से ही भारत भर में लगभग 3,800-4,000 लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों को जोड़ता है, जिससे वेब और मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से वास्तविक समय में इन्वेंट्री अपडेट, डोनर समन्वय और शिविर की जानकारी मिलती है। इस एकीकृत प्लेटफॉर्म के भीतर दुर्लभ रक्त प्रकारों को चिह्नित करने से बैंकों द्वारा तेजी से डोनर की खोज, बेहतर रोगी मिलान और सक्रिय स्टॉक प्रबंधन संभव होगा।

- एकीकरण से मरीजों को काफी लाभ होगा: संगत दुर्लभ रक्त तक तेजी से पहुंच, सुव्यवस्थित राष्ट्रीय स्तर की खोज क्षमताएं, और एलोइम्यूनाइजेशन का कम जोखिम - कई एंटीजन बेमेल वाले मरीजों के लिए महत्वपूर्ण। थैलेसीमिया के मामलों में एलोइम्यूनाइजेशन की दरें वर्तमान में 8-18% हैं, और इस प्रणाली से मामूली एंटीजन मिलान को शामिल करके ऐसे जोखिमों को कम करने की उम्मीद है।

Key Points:-

(i) दुर्लभ रक्त नेटवर्क को डिजिटल करके, भारत अब खंडित स्थानीय खोजों से दूर एक संवेदनशील, केंद्रीकृत बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ सकता है जो आपात स्थिति के दौरान दुर्लभ रक्त को जुटाने में सक्षम है - यहां तक कि राज्य-पार या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। रक्त बैंकों को दुर्लभ रक्त स्टॉक, दाता की उपलब्धता और वास्तविक समय रसद समन्वय की निगरानी के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड प्राप्त होंगे।

(ii) अपने वादे के बावजूद, इस पहल को मामूली एंटीजन टाइपिंग के लिए अपर्याप्त उपकरण, कई ब्लड बैंकों में असमान डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी जैसी बाधाओं को दूर करना होगा। देश भर में विस्तार करने के लिए, बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, IT एकीकरण और नियामक निरीक्षण में निरंतर निवेश आवश्यक होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी 4,000+ ब्लड बैंक इकाइयाँ ऑनलाइन हों और उनका

नियमित रूप से ऑडिट किया जाए।

(iii) भारत की पहली दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री का ई-रक्तकोष के साथ शुभारंभ और एकीकरण देश के रक्ताधान ढांचे में एक परिवर्तनकारी कदम है। राष्ट्रीय स्तर पर दुर्लभ रक्त की दृश्यता और वास्तविक समय में मिलान को सक्षम करके, यह पहल दुर्लभ रक्त की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए तेज़, सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत देखभाल का वादा करती है। निरंतर समर्थन और विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्लभ रक्त की अनुपलब्धता के कारण कोई जीवन न खो जाए।

INTERNATIONAL

1. PM नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए; साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया और 51वें जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।



प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15-19 जून 2025 तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा की, भारत की वैश्विक साझेदारी को मजबूत किया और कनाडा में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

- PM मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस के निमंत्रण पर 15-16 जून 2025 तक साइप्रस की दो दिवसीय यात्रा के साथ अपने दौरे की शुरुआत की, जो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा

के बाद दो दशकों में साइप्रस की पहली भारतीय प्रधान मंत्री यात्रा है। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान, PM मोदी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया।

- वित्तीय क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के GIFT सिटी स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) इंटरनेशनल एक्सचेंज और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज (CSE) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) शुरू करने के लिए यूरोबैंक साइप्रस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा।

- 16-17 जून 2025 को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जोसेफ कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी कनाडा गए। दोनों नेताओं ने रणनीतिक चर्चा की और लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद राजनयिक चैनलों को बहाल करने के लिए एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों को फिर से नियुक्त करने पर सहमति जताई, जिससे पूर्ण-स्पेक्ट्रम द्विपक्षीय संबंधों के पुनर्निर्माण के उनके इरादे की पुष्टि हुई।

Key Points:-

(i) कनाडा में, प्रधानमंत्री मोदी ने 51वें G7 (ग्रुप ऑफ सेवन) शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहाँ भारत को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। कनाडा द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, आर्थिक लचीलापन और डिजिटल शासन सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की भागीदारी ने बहुपक्षीय वैश्विक नेतृत्व मंचों के साथ उसके बढ़ते जुड़ाव को दर्शाया।

(ii) इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के निमंत्रण पर 18 जून 2025 को क्रोएशिया की यात्रा की, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा क्रोएशिया गणराज्य की पहली यात्रा थी। दोनों देशों ने कृषि, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा

अकादमिक और भाषाई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज़ाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना से संबंधित चार प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

(iii) बहु-राष्ट्र दौरे ने भारत की बहु-वेक्टर कूटनीति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया में हुई मुलाकातों ने वित्त, डिजिटल भुगतान, शिक्षा, संस्कृति और रणनीतिक कूटनीति में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को गहरा करने के भारत के इरादे को दर्शाया, जिससे भारत का अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ा।

2. ECB रिपोर्ट के अनुसार "अमेरिकी डॉलर के बाद सोना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बन गया है"।



2024 के अंत में आधिकारिक रिजर्व संरचना पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की रिपोर्ट के अनुसार, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, सोना यूरो को पीछे छोड़कर दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व संपत्ति बन गया है, जो अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरे स्थान पर है।

- वर्ष 2024 के अंत तक, वैश्विक आधिकारिक भंडार में सोने का हिस्सा 20% हो जाएगा - यूरो से आगे निकल जाएगा, जिसका हिस्सा 16% था, जबकि अमेरिकी डॉलर 46% पर हावी रहा। अन्य मुद्राओं ने सामूहिक रूप से लगभग 18% हिस्सा बनाया।

- केंद्रीय बैंकों ने 2024 में रिकॉर्ड गति से सोने की खरीद जारी रखी, 1,000 टन से अधिक का अधिग्रहण किया -

2010 के औसत वार्षिक मात्रा का दोगुना - कुल वैश्विक होलिंग्स को लगभग 36,000 टन तक बढ़ा दिया, जो 1960 के दशक के मध्य ब्रेटन वुड्स युग के बाद से नहीं देखा गया स्तर है।

Key Points:-

(i) 2024 में सोने की कीमतें लगभग 30% बढ़कर 3,500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गईं, जो भू-राजनीतिक तनावों - विशेष रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष - से प्रेरित है, क्योंकि केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति, प्रतिबंधों और मुद्रा जोखिमों के खिलाफ बचाव के लिए सोने का इस्तेमाल किया था।

(ii) 60 केंद्रीय बैंकों के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग दो-तिहाई ने मुख्य रूप से विविधीकरण के लिए सोने को अपनाया, जबकि 40% ने भू-राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षा का हवाला दिया। सोने की कीमतों और वास्तविक पैदावार के बीच ऐतिहासिक व्युत्क्रम सहसंबंध 2022-24 की अवधि के दौरान टूट गया, जो भू-राजनीतिक बचाव के रूप में सोने के उदय को दर्शाता है।

(iii) भंडार में कमी के बावजूद, यूरो अंतरराष्ट्रीय वित्त में महत्वपूर्ण बना हुआ है। ECB के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में यूरो-मूल्यवान ऋण जारी करने में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है - जो 2008 के संकट के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है - वैश्विक बॉन्ड बाजारों में यूरो की स्थायी भूमिका को उजागर करता है, भले ही केंद्रीय भंडार सोने की ओर बढ़ रहा हो।

3. टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 के शीर्ष 100 में चार भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए।



18 जून, 2025 को टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) ने अपनी यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 जारी की, जिसमें चार भारतीय विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर अपने प्रदर्शन के लिए वैश्विक शीर्ष 100 में शामिल हुए।

● तमिलनाडु के कोयंबटूर में अमृता विश्व विद्यापीठ ने विश्व स्तर पर 41वीं रैंकिंग प्राप्त करके भारत का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जबकि पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) ने 48वां स्थान प्राप्त किया, जिससे दोनों संस्थान द इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में वैश्विक शीर्ष 50 में शामिल हो गए, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में योगदान के आधार पर विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करता है।

● इनके अलावा, कर्नाटक के मैसूर स्थित JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (JSS AHER) को 56वां स्थान मिला है, तथा हिमाचल प्रदेश के बाझोल स्थित शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज को 96वां स्थान मिला है, जिससे सतत विकास प्रभाव के लिए वैश्विक शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत का प्रतिनिधित्व पूरा हो गया है।

Key Points:-

(i) टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के 2025 संस्करण में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी (ऑस्ट्रेलिया) लगातार चौथे साल वैश्विक सूची में शीर्ष पर रही, जिसने 98.7 का स्कोर हासिल किया, उसके ठीक बाद मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी (यूके) 98.4 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रही। रैंकिंग में लैंगिक

समानता, जलवायु कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित 17 संयुक्त राष्ट्र SDGs में प्रदर्शन के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है।

(ii) क्यूंगपुक नेशनल यूनिवर्सिटी (दक्षिण कोरिया) 97.8 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी और तस्मानिया यूनिवर्सिटी दोनों ने 97.7 अंक अर्जित कर चौथा स्थान साझा किया, जो उच्च शिक्षा स्थिरता मानकों में ऑस्ट्रेलिया की निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाता है।

(iii) टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) एक UK-आधारित वैश्विक रैंकिंग एजेंसी है जिसका मुख्यालय लंदन में है, और इसके वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन गिल हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए SDG के आधार पर समाज में विश्वविद्यालय के योगदान को मापने के लिए इम्पैक्ट रैंकिंग पहली बार 2019 में शुरू की गई थी।

BANKING & FINANCE

1. RBI के नए परियोजना वित्त मानदंड NBFCs को राहत प्रदान करते हैं, क्योंकि REC और PFC वृद्धि के लिए तैयार हैं।



जून 2025 के मध्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अंतिम परियोजना वित्त निर्देश, 2025 जारी किया, जिसमें बुनियादी ढाँचे और वाणिज्यिक अचल संपत्ति ऋणों के लिए प्रावधान मानदंडों को काफी आसान बनाया गया। यह सुधार बैंकों और

REC और PFC जैसी NBFC को बहुत ज़रूरी विनियामक स्पष्टता और राहत प्रदान करता है।

● 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी नए मानदंडों के तहत, RBI ने निर्माणाधीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को प्रस्तावित 5% से घटाकर 1% कर दिया है, और निर्माणाधीन वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए 2.5% से घटाकर 1.25% कर दिया है।

● व्यवधान से बचने के लिए मौजूदा परियोजनाएं पुराने नियमों के तहत ही रहेंगी groww.in +4 reuters.com +4 business-standard.com +4 . निर्देशों में आरंभ तिथि (DCCO) के लिए विस्तार को 3 वर्ष (बुनियादी ढांचे) और 2 वर्ष (गैर-बुनियादी ढांचे) पर सीमित कर दिया गया है।

● नया ढांचा कई पुराने परिपत्रों की जगह एक सुसंगत, सिद्धांत-आधारित व्यवस्था लेकर आया है, जिसमें बैंक, NBFCs और सहकारी ऋणदाता शामिल हैं। इसमें आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और जोखिम सीमा, अनुपालन जटिलता को कम करने और ऋण पर्यावरण की भविष्यवाणी को बढ़ावा देने के बारे में दिशा-निर्देश शामिल हैं।

Key Points:-

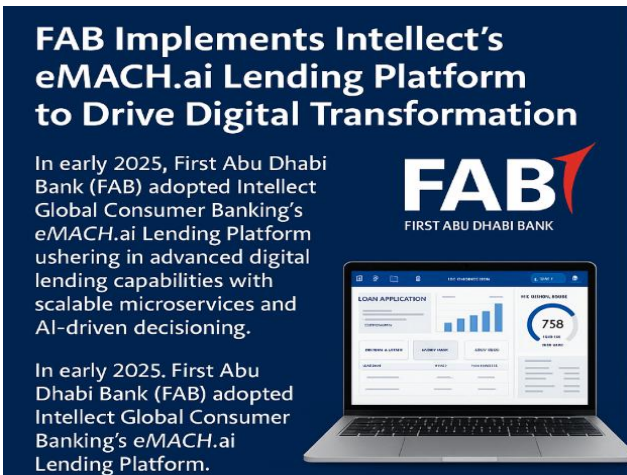
(i) घोषणा के बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (REC) के शेयरों में 3.3% से 6% तक की उछाल आई, जो निवेशकों की आशावादिता को दर्शाता है। मोतीलाल ओसवाल जैसे विश्लेषकों ने PFC के लिए ₹485 और REC के लिए ₹460 के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीद रेटिंग की पुष्टि की है।

(ii) बाजार टिप्पणीकारों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि मानदंड न्यूनतम लाभप्रदता प्रभाव डालते हैं, साथ ही सबसे खराब स्थिति में भी प्रावधान वृद्धि 1% से कम रहती है। नरम नियमों को दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे के वित्त के लिए प्रमुख बाधाओं को दूर करने के रूप में देखा जाता है, जो वित्त वर्ष 26 में प्रत्याशित ऋण वृद्धि का समर्थन करता है।

(iii) RBI की नीति गवर्नर संजय मल्होत्रा के तहत व्यापक

एजेंडे में फिट बैठती है, जिसमें छोटे वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण को आसान बनाना और गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए उधार मानदंडों को कैलिब्रेट करना शामिल है। अक्टूबर 2025 से परियोजना वित्त मानदंडों के कार्यान्वयन से ऋणदाताओं को बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट क्षेत्रों को निरंतर वित्तपोषण सुनिश्चित करते हुए समायोजित करने का समय मिलता है।

2. फर्स्ट अबू धाबी बैंक (FAB) ने डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए इंटेलेक्ट के eMACH.ai ऋण प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित किया।



2025 की शुरुआत में, फर्स्ट अबू धाबी बैंक (FAB) ने इंटेलेक्ट ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग के eMACH.ai लेंडिंग प्लेटफॉर्म को अपनाया, जिससे स्केलेबल माइक्रोसर्विसेज और AI-संचालित निर्णय के साथ उन्नत डिजिटल ऋण क्षमताओं की शुरुआत हुई।

- FAB का eMACH.ai ऋण मंच बैंक को एक संयोजित, क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर से सुसज्जित करता है जो विविध ऋण उत्पादों - खुदरा, SME, कॉर्पोरेट और कृषि - को एक प्रणाली के तहत उत्पत्ति, सेवा, ऋण और संपार्श्विक प्रबंधन को एकीकृत करने का समर्थन करता है।

- "हमेशा चालू, हमेशा जागरूक" डिजाइन का लाभ उठाते हुए, प्लेटफॉर्म 360-डिग्री वास्तविक समय ग्राहक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, क्रेडिट निर्णयों को स्वचालित

करता है, तत्काल DIY उत्पाद निर्माण की अनुमति देता है, और फिनटेक और क्रेडिट ब्यूरो के साथ सहज APIs एकीकरण प्रदान करता है।

- यह डिजिटल परिवर्तन FAB के विकास को स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ समर्थन देता है, जो प्रति सेकंड 10 मिलियन से अधिक खातों और हजारों लेनदेन को संभालने में सक्षम है। यह दक्षता बढ़ाता है, लागत में कटौती करता है, और वास्तविक समय मार्जिन ट्रेकिंग और स्वचालित ऋण सेवा के माध्यम से जोखिम प्रबंधन को तेज करता है।

Key Points:-

(i) FAB में eMACH.ai का कार्यान्वयन अन्य क्षेत्रों में इसके सफल रोल-आउट के बाद हुआ है: मध्य पूर्व और अफ्रीका में, मंच ने 329 माइक्रोसर्विसेस और 1,757 APIs के साथ एक संयोजन योग्य, इवेंट-संचालित फैब्रिक पर खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग संस्थानों को सशक्त बनाया।

(ii) इसी तरह की तैनाती में नेशनल बैंक ऑफ फुजैराह शामिल है, जिसने eMACH.ai के माध्यम से कॉर्पोरेट बैंकिंग को डिजिटल बना दिया, और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख बैंकों ने डिजिटल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया, जिससे प्रौद्योगिकी में वैश्विक विश्वास पर प्रकाश डाला गया।

(iii) FAB द्वारा eMACH.ai लेंडिंग प्लैटफॉर्म को अपनाना बैंक के डिजिटल रोडमैप में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को मजबूत करती है, जिससे उत्पाद लॉन्च करने में तेजी आती है, क्रेडिट संबंधी गहरी जानकारी मिलती है और क्षेत्रीय और वैश्विक डिजिटल बैंकिंग मानकों के साथ बेहतर तालमेल होता है।

ECONOMY & BUSINESS

1. टाटा Elxsi और इंफिनिऑन ने भारत के लिए अनुप्रयोग-तैयार EV समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की।



जून 2025 में, बेंगलुरु स्थित टाटा एलेक्सी ने भारत के तेजी से बढ़ते EV बाजार के लिए अनुकूलित अनुप्रयोग-तैयार इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सिस्टम को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए जर्मनी की इंफिनियन टेक्नोलॉजीज AG के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- टाटा समूह के तहत डिजाइन और प्रौद्योगिकी सेवाओं में एक वैश्विक नेता टाटा एलेक्सी और एक शीर्ष अर्धचालक नवप्रवर्तक इंफिनियन टेक्नोलॉजीज एजी, भारतीय दोपहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनुकूलित उच्च वोल्टेज इनवर्टर, स्केलेबल बैटरी प्रबंधन प्रणाली (BMS), द्विदिश ऑनबोर्ड चार्जर और थर्मल प्रबंधन प्रणाली सहित ऑटोमोटिव-ग्रेड EV घटकों के निर्माण पर सहयोग करेंगे।

- यह साझेदारी नीति आयोग के राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता लक्ष्यों के अनुरूप है - जिसका लक्ष्य 2030 तक दोपहिया और तिपहिया वाहनों का 80 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक वाहनों का 70 प्रतिशत विद्युतीकरण करना है - और साथ ही भारत में ईवी बिक्री में वृद्धि (2024 में सालाना आधार पर 25-30 प्रतिशत, 2W/3W बाजारों में 28 प्रतिशत वृद्धि) को संबोधित करना है।

- मुख्य ध्यान ISO 26262 कार्यात्मक सुरक्षा मानकों के अनुसार ASIL-D अनुपालन प्राप्त करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि EV सबसिस्टम शीर्ष-स्तरीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। Infineon सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) सेमीकंडक्टर घटक, माइक्रोकंट्रोलर और

एकीकृत सर्किट प्रदान करेगा, जबकि टाटा एलेक्सी सिस्टम एकीकरण, सत्यापन और डिज़ाइन अनुकूलन को संभालता है।

Key Points:-

(i) मुख्यधारा के वाहनों से परे, साझेदार अपने EV समाधानों को इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (eVTOL) वाहनों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और ऑफ-हाइवे क्षेत्रों तक विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं - जो भविष्य की गतिशीलता चुनौतियों के लिए तत्परता का संकेत है।

(ii) टाटा एलेक्सी के ऑटोमोटिव प्रमुख, नंबी गणेश ने इस बात पर जोर दिया कि कई मौजूदा ईवी समाधान पहले से ही इंफिनिऑन चिप्स पर निर्मित हैं; समझौता ज्ञापन प्रणाली-स्तरीय संरेखण को गहरा करेगा और भारतीय बाजार के लिए बाजार में जाने की समयसीमा में तेजी लाएगा।

(iii) इंफिनिऑन टेक्नोलॉजीज एशिया पैसिफिक में ऑटोमोटिव के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केनेथ लिम ने कहा कि यह सहयोग टाटा एलेक्सी की डिजाइन विशेषज्ञता को इंफिनिऑन के सेमीकंडक्टर नवाचार के साथ मिलाकर भारत के विद्युतीकरण प्रयासों को मजबूत करता है - अंततः लागत-अनुकूलित, सुरक्षित और स्केलेबल EV सिस्टम प्रदान करता है।

MOUs and Agreement

1. गुजरात सरकार ने वैश्विक स्तर पर MSME ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अमेज़न इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



5 जून, 2025 को गुजरात सरकार के एमएसएमई आयुक्तालय ने अहमदाबाद में एक्सपोर्ट कनेक्ट 2025 कार्यक्रम के दौरान अमेज़न इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अमेज़न ग्लोबल सेलिंग का लाभ उठाकर हज़ारों स्थानीय MSMEs को सशक्त बनाना है।

- इस समझौते में कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों और ऑनबोर्डिंग शिविरों के आयोजन के लिए एक संयुक्त पहल की रूपरेखा दी गई है, जिसका उद्देश्य MSMEs को यह सिखाना है कि वे अमेज़न के 200 से अधिक देशों के बाज़ारों पर B2C ई-कॉमर्स निर्यात के माध्यम से कैसे पहुँचें और आगे बढ़ें। निर्यातकों के बीच चल रहे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अमेज़न गांधीनगर में एक निर्यात समुदाय केंद्र की स्थापना का भी समर्थन करेगा।

- एक अनूठा कैस्केडिंग प्रशिक्षण मॉडल लागू किया जाएगा: अमेज़न इंडिया सबसे पहले गुजरात एमएसएमई आयुक्तालय के अधिकारियों को निर्यात प्रोटोकॉल और ई-कॉमर्स संचालन पर प्रशिक्षण देगा। ये प्रशिक्षित अधिकारी फिर स्थानीय MSMEs के लिए राज्यव्यापी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे, जिससे राज्य स्तर से ही व्यापक ज्ञान हस्तांतरण संभव हो सकेगा।

Key Points:-

(i) गुजरात भारत के शीर्ष निर्यातक राज्यों में से एक है, जो साझेदारी को अत्यधिक रणनीतिक बनाता है। यह सहयोग

स्थानीय व्यवसायों को डिजिटल बनाने और वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित है। अमेज़न ग्लोबल सेलिंग के माध्यम से, MSMEs को लॉजिस्टिक्स और क्रॉस-बॉर्डर अनुपालन में भारी निवेश के बिना तेजी से बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी।

(ii) MoU का लक्ष्य सैकड़ों हज़ार MSMEs को डिजिटल बनाना है - अकेले गुजरात में 36 लाख से ज़्यादा MSMEs हैं - जिससे कई MSMEs वैश्विक निर्यातक बन सकते हैं। इसका उद्देश्य राज्य भर में डिजिटल विकास को गति देना, राजस्व बढ़ाना, रोज़गार पैदा करना और राज्य के “मेक इन गुजरात” ब्रांड को वैश्विक स्तर पर मज़बूत करना है।

(iii) गुजरात-अमेज़न समझौता ज्ञापन ज़मीनी स्तर के MSMEs को वैश्विक व्यापार में भाग लेने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेज़न की वैश्विक निर्यात क्षमताओं को संरचित राज्य-स्तरीय समर्थन और प्रशिक्षण के साथ मिलाकर, इस पहल से गुजरात के छोटे व्यवसायों के लिए नए अवसरों के द्वार खुलने, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और राज्य की निर्यात क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

2. भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए RITES और हिंदुस्तान कॉपर इंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



6 जून, 2025 को, RITES Ltd, एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ने खान मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला का सह-विकास करना, भारत की औद्योगिक लचीलापन को मजबूत करना और आयात निर्भरता को कम करना है।

- गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन भारत और विदेश में धातुओं और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, निष्कर्षण, शोधन और उत्पादन में संयुक्त प्रयासों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें खनिज-ब्लॉक नीलामी में भागीदारी और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करने के लिए खनन कार्यों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को शामिल किया गया है।

- RITES HCL की सहायता के लिए इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और परिवहन नियोजन में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी। यह परियोजना नियोजन, मल्टीमॉडल परिवहन अवसंरचना, रोलिंग स्टॉक प्रावधान और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को कवर करने वाली एंड-टू-एंड कंसल्टेंसी प्रदान करेगी, जिसका उद्देश्य खनन दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है।

- यह सहयोग भारत के खनिज सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रयासों के अनुरूप है। घरेलू खनिज मूल्य श्रृंखला को मजबूत करके, यह आयात जोखिमों और आपूर्ति-श्रृंखला कमजोरियों को कम करते हुए अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का समर्थन करता है।

Key Points:-

(i) MoU की घोषणा के बाद, RITES के शेयरों में इंस्ट्राडे में 3% तक की उछाल आई, जो निवेशकों की तेजी का संकेत है। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में भी करीब 2% की बढ़त देखी गई, क्योंकि बाजारों ने इस घोषणा को महत्वपूर्ण-खनिज रणनीति को मजबूत करने के संकेत के रूप में

स्वीकार किया।

(ii) यह समझौता वित्तीय सहयोग और जोखिम-साझाकरण के लिए एक लचीला, परियोजना-वार ढांचा स्थापित करता है। दोनों कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नीलामी को रोकने, खनन और परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और प्रत्येक परियोजना के लिए शर्तों को अंतिम रूप देने में समन्वय करें। पूर्ण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए विनियामक अनुमोदन, निवेश और परिचालन समन्वय सहित कुशल निष्पादन की आवश्यकता होगी।

(iii) RITES-HCL समझौता ज्ञापन भारत में एक एकीकृत महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। HCL की खनन विशेषज्ञता को राइट्स की रसद और इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ जोड़कर, यह साझेदारी भारत की खनिज सुरक्षा को बढ़ाती है, रणनीतिक उद्योगों का समर्थन करती है, और बाजार मूल्यांकन में सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित होती है - जो देश की आपूर्ति-श्रृंखला रणनीति में निवेशकों के विश्वास का संकेत देती है।

3. बिहार मंत्रिमंडल ने UDAN योजना के तहत छह क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए AAI के साथ 150 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।



17 जून, 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की उड़ान (उड़े देश

का आम नागरिक) योजना के तहत छह नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ 150 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य सस्ती क्षेत्रीय हवाई यात्रा को बढ़ावा देना है।

- MoU में छह शहर शामिल हैं- मधुबनी, बीरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर और सहरसा- प्रत्येक हवाई अड्डे की अनुमानित लागत लगभग ₹25 करोड़ है। ये स्थल अप्रैल 2025 में स्वीकृत पूर्व व्यवहार्यता अध्ययनों का हिस्सा थे, जो निर्माण के लिए आधार तैयार कर रहे थे।

- यह पहल भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसके तहत उड़ान के तहत अगले दशक में 120 नए हवाई अड्डे जोड़े जाएंगे, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की सेवा के लिए नेटवर्क का विस्तार होगा और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को सहायता मिलेगी।

- इस विस्तार से पर्यटन को (विशेष रूप से वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के आसपास) काफी लाभ मिलने, आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि होने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन मिलने तथा वंचित क्षेत्रों में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

Key Points:-

(i) छह हवाई अड्डों के लिए कुल ₹150 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है, जिनमें से प्रत्येक को ₹25 करोड़ मिलेंगे। नदी अध्ययन के लिए ₹2.58 करोड़ और सभी के लिए आवास योजना के तहत ₹224 करोड़ जैसे अतिरिक्त राज्य बजट आवंटन व्यापक बुनियादी ढांचे के उन्नयन को दर्शाते हैं।

(ii) AAI निर्माण का नेतृत्व करेगा और भूमि उपलब्धता की पुष्टि प्राप्त करेगा। समझौता ज्ञापन चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है, जिसके लिए समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय और आवधिक ऑडिट की आवश्यकता होती

है।

SPORTS

1. भारत ने 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 100-दिवसीय उलटी गिनती शुरू करने के लिए "विराज" Mascot और प्रतीक पेश किया।



20 जून 2025 को पैरा ओलंपिक समिति भारत (Paralympic Committee of India – PCI) ने नई दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए आधिकारिक शुभंकर 'विराज' और प्रतीक चिह्न (Logo) का अनावरण किया। यह कार्यक्रम चैंपियनशिप के "100 दिन बाकी" अभियान की शुरुआत के रूप में आयोजित किया गया।

- अशोक होटल में एक उच्च प्रोफ़ाइल समारोह के दौरान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने PCI के मुख्य संरक्षक वनथी श्रीनिवासन (विधानसभा सदस्य) और ब्रांड एंबेसडर कंगना रनौत सहित प्रतिष्ठित अतिथियों के सामने औपचारिक रूप से शुभंकर और प्रतीक चिह्न लॉन्च किया, जिसमें समावेशिता और उत्कृष्टता के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

- इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आशीष सूद, खेल सचिव हरी रंजन राव और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स प्रमुख पॉल फिट्ज़गेराल्ड जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उन्होंने भारत की तैयारियों की सराहना की और कहा कि

यह आयोजन “दुनिया का सबसे समावेशी और ऊर्जावान संस्करण” होगा।

Key Points:-

(i) अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति (IPC) के अध्यक्ष और दो बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेन्द्र झाझरिया ने कहा कि शुभंकर 'वीराज' और प्रतीक चिह्न पैरा-एथलीट्स के आत्मगौरव, शक्ति और असीम क्षमता का प्रतीक हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 2,500 से ज्यादा एथलीट्स भाग लेंगे, जिससे यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा पैरा खेल आयोजन बन जाएगा।

(ii) 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाली इस 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप से भारत की आयोजन क्षमताओं का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन होगा। यह आयोजन पैरा खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा और समावेशी एवं सुलभ खेल व्यवस्था की दिशा में एक स्थायी विरासत छोड़ जाएगा।

2. जसप्रीत बुमराह SENA देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई तेज गेंदबाज बन गए।



3 फरवरी, 2024 को विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट में, जसप्रीत बुमराह सिर्फ 34 मैचों में 150 टेस्ट विकेट लेने की उपलब्धि तक पहुंच गए, और SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले एशियाई तेज गेंदबाज बन गए।

● जसप्रीत बुमराह ने भारतीय दिग्गज कपिल देव को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 39 टेस्ट मैचों में इतने ही विकेट लिए थे, जिससे भारतीय तेज गेंदबाजी में एक नया युग शुरू हुआ। स्पिनर आर अश्विन (29 टेस्ट) और रवींद्र जडेजा (32 टेस्ट) ने इस मुकाम को तेजी से हासिल किया, लेकिन बुमराह ऐसा करने वाले सबसे तेज भारतीय तेज गेंदबाज हैं।

● एशियाई संदर्भ में, बुमराह पाकिस्तान के वकार यूनिस के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 1994 में 27 मैचों में 150 टेस्ट विकेट हासिल किए थे। उन्होंने इमरान खान (37 टेस्ट) और शोएब अख्तर (37 टेस्ट) को भी पीछे छोड़ दिया, जिससे उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे तेज एशियाई खिलाड़ियों में अपना स्थान मजबूत कर लिया।

Key Points:-

(i) विशाखापत्तनम टेस्ट में बुमराह ने बेन स्टोक्स को आउट करके अपना 150वां विकेट हासिल किया, जो भारत की दूसरी पारी के गेंदबाजी आक्रमण के दौरान मील का पत्थर साबित हुआ। इस मील के पत्थर पर उनका स्ट्राइक रेट ~44.75 और औसत ~20.29 रहा, जो उनके निरंतर प्रभाव को दर्शाता है।

(ii) अब तक बुमराह ने SENA देशों में 21.02 की प्रभावशाली औसत से 145 विकेट लिए हैं, जिसमें 7 बार पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड शामिल है और वे उन परिस्थितियों में सबसे सफल भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं।

(iii) बुमराह की उपलब्धि विदेशों में भारतीय तेज गेंदबाजों की बढ़ती ताकत को रेखांकित करती है। असाधारण नियंत्रण, रिवर्स स्विंग क्षमताओं और घातक यॉर्कर के साथ, वह भारतीय तेज गेंदबाजी को फिर से परिभाषित कर रहे हैं - और 200 टेस्ट विकेटों का पीछा करने और SENA परिस्थितियों में प्रभुत्व सहित आगे के रिकॉर्ड के लिए ट्रैक पर हैं।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून 2025 को संक्रांति उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।



21 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, जिसमें वैश्विक धर्मों और जातीय परंपराओं में इसके खगोलीय, सांस्कृतिक और कृषि महत्व पर प्रकाश डाला गया।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 20 जून, 2019 को संकल्प A/RES/73/300 को अपनाया, जिसमें 21 जून को संक्रांति और विषुव तथा पृथ्वी के मौसमी चक्रों, त्यौहारों और कृषि लय पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक दिवस घोषित किया गया। यह संकल्प ब्रह्मांडीय घटनाओं और मानव संस्कृति के बीच संबंध पर जोर देता है, जिससे प्राकृतिक समय-निर्धारण प्रणालियों के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है।

- ये बदलाव पृथ्वी के 23.5 डिग्री के अक्षीय झुकाव के कारण होते हैं। जून संक्रांति के दौरान, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की अधिकतम रोशनी होती है और गर्मी शुरू हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी शुरू हो जाती है। दिसंबर में, पैटर्न उलट जाता है, जो मौसमी परिवर्तनों को परिभाषित करने और पारिस्थितिकी, कृषि और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करने में अक्षीय झुकाव के महत्व को उजागर करता है।

Key Points:-

(i) विषुव (equinox) तब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है।

(ii) यह शब्द लैटिन से लिया गया है: "एक्स" (बराबर) और "नॉक्स" (रात)। दो वार्षिक विषुव हैं- मार्च विषुव, जो 20 मार्च के आसपास होता है, वसंत की शुरुआत का संकेत देता है, जबकि सितंबर विषुव, जो 23 सितंबर या उसके आसपास होता है, शरद ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है। दोनों विषुव वर्ष को सममित रूप से विभाजित करते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर दिन के उजाले और अंधेरे का संतुलन बना रहता है।

(iii) संयुक्त राष्ट्र खगोलीय विरासत की समझ को गहरा करने, प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का जश्न मनाने के लिए इस दिन को मनाने को प्रोत्साहित करता है जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मील के पथर के रूप में संक्रांति और विषुव का सम्मान करते हैं। संक्रांति के उत्सव के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य आधुनिक समाज को इन ब्रह्मांडीय लय के साथ फिर से जोड़ना और मौसमी संतुलन और पर्यावरणीय चेतना के प्रति सम्मान बढ़ाना है।

2. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025, 23 जून को "लेट्समूव?" अभियान के साथ मनाया गया ताकि दुनिया भर में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जा सके।



हर साल 23 जून को ओलंपिक आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाता है, जो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की याद दिलाता है। 2025 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ शुरू की गई वैश्विक थीम "लेट्स मूव?" निष्क्रियता से निपटने के लिए सामुदायिक शारीरिक गतिविधि का आग्रह करती है।

- ओलंपिक दिवस की अवधारणा 1947 में शुरू हुई थी, जब चेकोस्लोवाकिया के डॉ. जोसेफ ग्रस ने स्टॉकहोम में IOC के 41वें सत्र में इसका प्रस्ताव रखा था। जनवरी 1948 में सेंट मोरिट्ज़ में 42वें सत्र में इस पहल को मंजूरी दी गई और 23 जून 1948 को नौ देशों में इसकी शुरुआत की गई।

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 1894 में पेरिस के सोरबोन में बैरन पियरे डी कुबर्टिन द्वारा IOC की स्थापना का प्रतीक है। अब 150 से अधिक देशों में मनाया जाने वाला यह दिवस वैश्विक खेल और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य ओलंपिक मूल्यों - उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान - को बढ़ावा देता है।

- 2025 की थीम, "लेट्स मूव?", जिसे 17 जून को IOC और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया, खतरनाक निष्क्रियता स्तरों को संबोधित करती है: 3 में से 1 वयस्क और वैश्विक स्तर पर 80% से अधिक युवा अनुशंसित शारीरिक गतिविधि से चूक जाते हैं। अभियान स्वास्थ्य, समुदाय और खुशी को बढ़ावा देने के लिए साझा आंदोलन को प्रोत्साहित करता है।

Key Points:-

(i) इस दिन के मुख्य आकर्षणों में ओलंपिक डे रन शामिल हैं - 1.5 किमी फन रन से लेकर 10 किमी दौड़ तक की गैर-प्रतिस्पर्धी स्पर्धाएँ - जिनमें दुनिया भर की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ भाग लेती हैं। पहली बार 1987 में शुरू की गई, आज 160 से ज़्यादा NOCs बड़े पैमाने पर खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए इन आयोजनों का आयोजन करती हैं।

(ii) 2025 में, IOC ने WHO और सैमसंग और TCL जैसे वैश्विक प्रायोजकों के साथ-साथ रिलायंस फाउंडेशन और

अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन जैसे भारतीय साझेदारों के साथ साझेदारी की, और 50 से अधिक भारतीय शहरों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों, डिजिटल चुनौतियों और खेल स्थलों तक मुफ्त पहुंच के माध्यम से समुदायों को संगठित करने के लिए "लेट्समूव+1" लॉन्च किया।

(iii) यह आंदोलन इस बात पर जोर देता है कि खेल शारीरिक और सामाजिक दोनों तरह से जोड़ता है। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा, "खेल आनंद है... खेल लोगों को एक साथ लाता है," जबकि WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयसस ने इसे "स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग और लचीले समुदायों के लिए कम लागत वाला, उच्च प्रभाव वाला उपकरण" बताया।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. भारती स्पेस यूटेलसैट के उपग्रह विस्तार में ₹313 करोड़ का निवेश करेगी।



जून 2025 में, भारती एंटरप्राइजेज की अंतरिक्ष शाखा ने फ्रांसीसी उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसैट में 313 करोड़ रुपये (लगभग 31.4 मिलियन यूरो) के निवेश की घोषणा की, जो उपग्रह नेटवर्क विस्तार और ऋण में कमी के लिए 1.35 बिलियन यूरो की पूंजी जुटाने की व्यापक पहल का हिस्सा है।

- यूटेलसैट में भारती का निवेश पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में योगदान देता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा ऋण को कम करना तथा नए उपग्रह समूहों की स्थापना के लिए धन

जुटाना है - जिसमें भूस्थिर और निम्न-पृथ्वी-कक्षा (GEO-LEO) प्रणालियां शामिल हैं - जिससे वैश्विक उपग्रह अवसंरचना विकास को समर्थन मिलेगा।

● यह निवेश भारती की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के प्रति चल रही प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। 2023 में यूटेलसैट-वनवेब विलय के बाद - जहाँ भारती 21.2% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक के रूप में उभरी - नवीनतम निवेश रणनीतिक निरंतरता और वैश्विक उपग्रह कनेक्टिविटी उद्देश्यों को रेखांकित करता है।

Key Points:-

(i) यह धनराशि यूटेलसैट की अगली पीढ़ी के उपग्रह समूहों की तैनाती में तेजी लाएगी, जो ब्रॉडबैंड, IoT और उद्यम सेवाओं के लिए अनुकूलित होंगे, बैंडविड्थ क्षमता को बढ़ाएंगे, विलंबता को कम करेंगे और दुनिया भर में कम सेवा वाले क्षेत्रों में पहुंच को सक्षम करेंगे।

(ii) यूटेलसैट को भारती द्वारा दी जा रही निरंतर वित्तीय सहायता उसे वैश्विक उपग्रह संपर्क विस्तार के चौराहे पर खड़ा करती है - जो स्पेसएक्स के स्टारलिनक जैसे खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है - और अंतरिक्ष-तकनीक और डिजिटल अवसंरचना क्षेत्रों में भारत की आकांक्षाओं को मजबूत करती है।

(iii) इस वर्ष के अंत में पूंजी जुटाने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, यूटेलसैट तारामंडल रोलआउट में तेजी लाना शुरू कर देगा, जबकि भारती उपग्रह संचार में अपने प्रभाव को मजबूत करना जारी रखेगी - एक ऐसा कदम जो डिजिटल समावेशन, ग्रामीण कनेक्टिविटी और वाणिज्यिक ब्रॉडबैंड पहुंच को बढ़ा सकता है।

2. NASA के वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान को सौर मंडल के किनारे पर अत्यधिक गर्म "आग की दीवार" का सामना करना पड़ा।



पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर नासा के वॉयेजर 1 यान ने हेलियोपॉज़ पर एक पतले प्लाज़्मा खोल का पता लगाया है जिसका तापमान 30,000-50,000K तक पहुंच रहा है, जिसे "आग की दीवार" का उपनाम दिया गया है।

● वॉयेजर की ऐतिहासिक क्रॉसिंग: 1977 में लॉन्च किया गया, वॉयेजर 1 25 अगस्त 2012 को हेलियोपॉज़ को पार करने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया, जिसने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया और बाद में अपने उपकरणों के साथ "वॉल ऑफ़ फायर" की खोज की। इसका जुड़वां, वॉयेजर 2, 2018 में आया और उसी घटना को रिकॉर्ड किया।

● "आग की दीवार" क्या है? यह शब्द अति गर्म प्लाज़्मा के एक संकीर्ण क्षेत्र - लगभग 1 AU मोटा - का वर्णन करता है जहाँ बाहर की ओर बहने वाली सौर हवा धीमे अंतरतारकीय माध्यम से टकराती है। हालाँकि विद्युत रूप से आवेशित, यह अत्यंत कम घनत्व वाला रहता है, जो वॉयेजर के थर्मल शील्डिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है।

● वॉयेजर 1 के प्लाज़्मा, कॉस्मिक किरण और चुंबकीय सेंसर ने दीवार के तापमान में 30,000 और 50,000K (54,000-90,000°F) के बीच की वृद्धि दर्ज की, जिससे यह कई तारकीय सतहों से अधिक गर्म हो गई - जिससे नासा ने इसे कॉस्मिक ब्लास्ट फर्नेस नाम दिया।

Key Points:-

(i) दोनों वॉयेजरों ने पाया कि हीलियोपॉज़ के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र अंदर के सौर चुंबकीय क्षेत्र के साथ निकटता से संरेखित है, जो पिछले मॉडलों का खंडन करता है और हीलियोस्फीयर और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच एक मजबूत चुंबकीय संबंध का संकेत देता है।

(ii) गर्मी के बावजूद, कम कण घनत्व के कारण वॉयेजर 1 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह 22 घंटे की देरी से सिर्फ 160 बिट प्रति सेकंड की गति से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा संचारित करता है, जबकि इसके ऑनबोर्ड प्लूटोनियम-संचालित उपकरण न्यूनतम ऊर्जा के साथ काम करना जारी रखते हैं।

(iii) वॉयेजर के निष्कर्षों के आधार पर, नासा के आगामी इंटरस्टेलर मैपिंग और एक्सेलरेशन प्रोब (IMAP) को 2026 में लॉन्च करने की योजना है, ताकि हेलियोपॉज़ प्लाज़्मा डायनेमिक्स का अध्ययन किया जा सके। 400 AU तक पहुंचने और "वॉल ऑफ़ फायर" का अधिक विस्तार से मानचित्र बनाने के लिए एक भविष्य के इंटरस्टेलर प्रोब मिशन पर भी काम चल रहा है।

केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व (PTR) में 7 से 10 जून 2025 तक किए गए विस्तृत हर्पेटोफॉनल सर्वेक्षण में आठ नई प्रजातियों के रिकॉर्ड सामने आए - पांच उभयचर और तीन सरीसृप - जो पहले रिजर्व में दर्ज नहीं थे, जिससे पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक महत्व की पुष्टि हुई।

● सर्वेक्षण ने पीटीआर चेकलिस्ट में पाँच उभयचरों को जोड़ा: माइक्रोहाइला डेरली (डेरल का कोरस मेंढक), यूप्लिक्टिस केरला (केरल स्किटरिंग मेंढक), यूप्लिक्टिस जलधारा (जलधारा स्किटरिंग मेंढक), माइक्रोहाइला निलफामेरीन्सिस (निलफामेरी संकीर्ण-मुँह वाला मेंढक), और यूरेओटिफ्लस नारायणी (नारायण का सीसिलियन)। ये प्रजातियाँ पश्चिमी घाटों में काफी हद तक स्थानिक हैं और इस रिजर्व में पहली बार दर्ज की गई हैं।

● तीन सरीसृप प्रजातियों को भी हाल ही में प्रलेखित किया गया: सीनेमास्पिस रशीदी (रशीद डे गेको), द्रविड़ोगेको मेघमालायेंसिस (मेघमलाई द्रविड़ोगेको), और द्रविड़ोगेको बेडडोमी (बेडडोम का द्रविड़ोगेको)। ये छिपकलियाँ मुख्य रूप से अलग-थलग पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और PTR के भीतर सूक्ष्म आवास विविधता का संकेत देती हैं।

Key Points:-

(i) सर्वेक्षण में कुल मिलाकर 67 उभयचर प्रजातियाँ और 82 सरीसृप प्रजातियाँ रिजर्व में दर्ज की गईं। पाए गए उभयचरों में से लगभग 80% पश्चिमी घाट के स्थानिक थे, जो वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में इस क्षेत्र की भूमिका और वैज्ञानिक दस्तावेज़ीकरण और आवास संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करता है।

(ii) इस अभ्यास का नेतृत्व केरल वन विभाग (KFD), पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन (PTCF) और अरण्यकम नेचर फाउंडेशन (ANF) ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें शोधकर्ताओं, कॉलेज के छात्रों, वन अधिकारियों और स्थानीय स्वयंसेवकों सहित 150 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट के तहत कमज़ोर या संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत 12 प्रजातियों की मौजूदगी से संरक्षण का महत्व रेखांकित हुआ।

ENVIRONMENT

1. केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व सर्वेक्षण में आठ ऐसी हर्पेटोफॉनल प्रजातियों की खोज हुई है जिनका पहले पता नहीं था।



इनमें त्रावणकोर कछुआ (इंडोटेस्टुडो ट्रावंकोरिका) और केन कछुआ (विजयचेलिस सिल्वेटिका) शामिल हैं, जो पश्चिमी घाट में आवास के खतरे का सामना कर रहे हैं।

Static GK

Eutelsat	CEO : जीन-फ्रांस्वा फालचर	मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
NASA	CEO : जेनेट पेट्रो	मुख्यालय : वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
Kerala	मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन	राज्यपाल: राजेंद्र आर्लेकर
Paralympic Committee of India (PCI)	अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति : देवेन्द्र झाझरिया	मुख्यालय: नई दिल्ली
Amazon	CEO : एंडी जेसी	मुख्यालय: सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका
Cyprus	राष्ट्रपति : निकोस क्रिस्टोडौलिडेस	राजधानी : निकोसिया
the Times Higher Education (THE)	CEO : जॉन गिल	मुख्यालय : लंदन
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Karnataka	मुख्यमंत्री: सिद्धारमैया	राज्यपाल: थावर चंद गहलोत
Tata Elxsi	CEO : मनोज	मुख्यालय:

	राघवन	बेंगलुरु
MoE	केंद्रीय मंत्री: धर्मेन्द्र प्रधान	मुख्यालय: नई दिल्ली
Rail India Technical and Economic Service (RITES)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: श्री राहुल मिथल	मुख्यालय: गुरुग्राम
Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान